क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रेस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय
RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 322, शनिवार, 22 दिसम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

प.बंगाल : भाजपा के ''रथयात्रा' कार्यक्रम को मिली अनुमति

कोलकाता एजेंसी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सांप्रदायिक अशांति की आशंका के आधार पर मंजूरी नहीं देने के आदेश को दरकिनार करते हुए गुरुवार को भाजपा के ''रथयात्रा' कार्यक्रम को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती ने प्रदेश भाजपा को जिले में रैली के प्रवेश करने के तय समय से कम से कम 12 घंटे पहले जिला पुलिस अधीक्षकों को इसकी सूचना देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने पार्टी को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कानून का पालन करते हुए यात्रा निकाली जाए और सामान्य यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने कहा कि संपत्ति के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए याचिकाकर्ता भाजपा परोक्ष रुप से जिम्मेदार होगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बल तैनात करेगी कि कानून व्यवस्था का कोई उल्लंघन न हो। भाजपा ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से तीन ''रथयात्राएं' निकालने की योजना बनायी थी। इन रथों को करीब डेढ़ महीने में राज्य के 42 संसदीय क्षेत्रों से गुजरना था।

यूपी टीईटी के संशोधित रिजल्ट के बाद अंकों में आया है अंतर तो 69000 शिक्षक भर्ती के लिए नया आवेदन करने की जरूरत नहीं, पुराना आवेदन मान्य

लखनऊ एजेंसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणामों में संशोधन किया गया है। परिणाम संशोधन के बाद जिन अभ्यर्थियों के अंकों में अंतर आया है, उन्हें शिक्षक भर्ती के लिए नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पुराना आवेदन ही मान्य होगा। अब 69 हजार पदों पर सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में 19,852 अभ्यर्थी और बढ़ेंगे। इससे पहले 3,66,285 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब संशोधन के बाद टीईटी 2018 की प्राइमरी स्तर की परीक्षा में कुल 3,86,137 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में आवेदन की आखिरी तारीख भी दो दिन बढ़ा दी गई है। अब 22 दिसम्बर तक पंजीकरण, 23 दिसम्बर तक फीस जमा कर सकेंगे। वहीं 24 दिसम्बर को फार्म पूरी तरह से सबमिट किया जा सकेगा।

यूपीटीईटी का संशोधित रिजल्ट जारी, 20 हजार और पास हुए

इस तरह बनेगा शैक्षिक गुणांक

इस बार राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए कोई कट ऑफ नहीं तय किया है, लिहाजा इस परीक्षा के 60 फीसदी नंबर जोड़े जाएंगे। वहीं दसवीं, बारहवीं, स्नातक और बीटीसी/डीएड/बीएड के 10-10 फीसदी अंक जोड़े जाएंगे।

सीएम योगी ने कहा, भर्ती बोर्ड ने अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया तो चेयरमैन होंगे जिम्मेदार

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि भर्ती बोर्ड ने अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया तो उनके चेयरमैन सीधे जिम्मेदार होंगे। सीएम ने आज विधानसभा में शून्यकाल में बसपा के सुखदेव राजभर के प्रतियोगी परीक्षा में धांधली के आरोपों को खारिज किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में नकल कराने वाले साल्वर गैंग जो पहले से ही सक्रिय थे, आज सब पर कार्य हो रही है। 41,500 शिक्षक की भर्ती हो, पुलिस भर्ती की बात हो, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है। 50 हज़ार नई पुलिस की भर्ती चालू की गई है, पारदर्शी तरीके से भर्ती के लिए हमने इंटरव्यू की प्रणाली भी हमने समाप्त कर दी है। पहले की सरकारें इंटरव्यू में पास कराने के लिये लोग झोला लेकर वसूली करते थे। जो शिकायतें आई हैं उन सभी पर सरकार ने सख्त कार्यवाही भी की है, सचिव और अध्यक्ष के आपसी लड़ाई के चलते अधीनस्थ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है जिसको सरकार ने मान भी लिया है। किसी भी आयोग की परीक्षाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश को स्टे लिया गया था। 68,500 की भर्ती निकली गयी थी, जिसमें 41,500 पास हुए थे फिर से कापियां जांच कराई गयी है, इसमें अगर कोई गड़बड़ी सामने आई तो उनपर कार्यवाही की जायेगी।

इलाहाबाद : कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान संगम का विहंगम दृश्य।

बुलंदशहर हिंसा पर बयान देकर घिरे नसीरुद्दीन शाह बोले- 'मुझे गद्दार कहा जा रहा है'

नई दिल्ली। बुलंदशहर हिंसा पर बयान देकर घिरे नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुझे गद्दार कहा जा रहा है, मैंने अपने देश को लेकर चिंता व्यक्त की थी, मैं देश को प्यार करता हूं जो मेरा घर है। बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने बुलंदशहर हिंसा में देखा कि गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है न कि पुलिस ऑफिसर की मौत को। इसके बाद उनकी आलोचना हुई और अखिल भारत हिन्दू महासभा ने नसीरुद्दीन शाह से पूछा है कि 68 साल की उम्र में उन्हें अब क्यों डर लगा। वह सभी हिंदुओं को दोषी बताकर एकता और अखंडता को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस मामले पर अब नसीरुद्दीन शाह ने अब एक और बयान दिया है। नसीरुद्दीन शाह बोले- 'गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है',इसका जवाब देते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुझे गद्दार कहा जा रहा है, मैंने अपने देश को लेकर चिंता व्यक्त की थी, मैं देश को प्यार करता हूं जो मेरा घर है। शाह ने मॉब लिंचिंग को लेकर कहा था कि मुझे अपने बच्चों के लिए बेहद डर लगता है। अगर कहीं मेरे बच्चों को भीड़ ने घेर लिया और हिन्दू या मुसलमान के बारे में पूछा तो बच्चों के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी है। अखिल भारत हिन्दू महासभा के जिलाध्यक्ष और हिन्दू न्याय पीठ हिन्दू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि नसीरुद्दीन शाह ने जो किरदार फिल्म सरफरोश में निभाया था, वह आज उसी के जैसे लग रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर उन्हें देश में खतरा लगता है तो वह देश छोड़कर चले जाएं।

गोरखपुर के डॉक्टर ने पहाड़ से धक्का देकर प्रेमिका को मौत के घाट उतारा, छह महीने बाद हुआ खुलासा

गोरखपुर। यूपी एसटीएफ ने चर्चित राजेश्वरी श्रीवास्तव उर्फ राखी हत्याकांड मामले में गोरखपुर के आर्यन अस्पताल के मालिक डॉ डीपी सिंह व दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया, इसकी जानकारी यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने गोरखपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। डॉ डीपी सिंह का संबंध राजेश्वरी श्रीवास्तव से 2006-07 से था, राखी के पिता हरिराम श्रीवास्तव डॉ डीपी सिंह के अस्पताल में ही भर्ती थे जिसकी वजह से राखी का यहां आना जाना होता रहता था, लगातार अस्पताल में राखी के आने जाने से उनका संबंध बन गया फिर उन दोनों ने साल 2011 फरवरी में जनपद गोंडा में शादी कर ली,।

डॉ डीपी सिंह की पहली पत्नी उषा सिंह को उनकी शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनकी एक बेटी हुई जिसकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। राखी को डॉक्टर ने सरस्वतीपुरम, बिछिया, थाना शाहपुर गोरखपुर में एक मकान खरीद कर दिया

था, राखी की शादी साल 2018 के फरवरी में मनीष कुमार श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति से हो गई, शादी के बाद भी राखी का सम्बन्ध डॉक्टर के साथ बना रहा। जून में डा. डीपी सिंह राखी को लेकर नेपाल गये।

पोखरा में पहाड़ से राखी को डाक्टर ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर धक्का दे दिया था। जुलाई में राखी के भाई ने शाहपुर में गुमशुदगी का केस कराया था।

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने अमेठी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

अमेठी। सूबे मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने अमेठी के शुकुलबाजार के भटमऊ गांव पहुंचे। गांव में बने हैलीपैड पर जिलाधिकारी शकुंतला गौतम, पुलिस अधीक्षक अनुराग मौर्य, यूपीडा के प्रबन्धक राम बाबू,राज्य मंत्री सुरेश पासी, विधायक प्रतिनिधि अनन्त विक्रम, जिलाध्यक्ष उमाशंकर पांडे ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद बिना गार्ड ऑफ ऑनर लिए मुख्यमंत्री आगे बढ़ गए। उन्होंने स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात की। यहां से मुख्यमंत्री सीधे यूपीडा द्वारा बनाये गए पैकेज टू के ऑफिस पहुंचे। जहां भाजपा के पदाधिकारियों ने भी पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए।

गुरुगोविंद सिंह के बेटों की शहादत के मौके पर सिख ''पंज प्यारों' ने एक धार्मिक जुलूस का नेतृत्व किया।

››› बिहार शरीफ नाबालिग रेपकांड:

विधायक राजबल्लभ यादव को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा

पटना एजेंसी। बिहारशरीफ के चर्चित नाबालिग रेपकांड में राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने सजा सुनाई है। बता दें कि कोर्ट ने पिछले दिनों नाबालिग से रेप के आरोपित विधायक राजबल्लभ यादव सहित सुलेखा देवी, राधा देवी, टुन्नी कुमारी, संदीप सुमन और छोटी कुमार उर्फ अमृता को इस मामले में दोषी करार दिया था।

एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने दोषी ठहराया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए राज्य में मार्च 2018 में विशेष कोर्ट बनाया गया। इसी आदेश के आलोक में पटना सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट का

विशेष न्यायाधीश बनाया गया। बिहार के सभी जिलों की अदालतों में चल रहे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ करीब तीन सौ आपराधिक कांडों को इस कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। मार्च से अबतक विशेष कोर्ट ने 20 से अधिक आपराधिक मामलों का निपटारा किया। साक्ष्य के अभाव में कई आरोपी बरी हो गए। यह पहला आपराधिक कांड है, जिसमें विशेष कोर्ट ने दोषी ठहराया है।

बिहार शरीफ में वर्ष 2016 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

इस घटना के संबंध में बिहारशरीफ महिला थाने में 9 फरवरी 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने राजवल्लभ यादव समेत छह आरोपियों पर आरोप पत्र दाखिल किया था। बिहारशरीफ सिविल कोर्ट के पॉस्को कोर्ट ने 6 सितबंर 2016 को आरोप का गठन किया था। इसके बाद सरकार द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन की ओर से गवाही कराई। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर इस कांड को पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया। फिर सभी आरोपितों को बिहारशरीफ जेल से पटना के बेउर जेल भेज दिया गया। इसके बाद एमपी-एमलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। पटना हाईकोर्ट के एक आदेश पर प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी।

दो बच्चों का अपहरण, फिरौती नहीं मिलने पर एक को फावड़े से काट डाला, दूसरा गंभीर रूप से घायल

लखनऊ। उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना के कटका बाजार के पास से अपहृत दो स्कूली बच्चों को बदमाशों ने फावड़े से काट डाला। वारदात में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरा बच्चा लखनऊ के ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बदमाशों ने गुरुवार को गोसाईगंज थाना के कटका खानपुर से दोपहर में अपहृत बच्चों को कोतवाली नगर के करौदियां मोहल्ले में गोमती नदी के किनारे एक मकान में रखा था। उसके बदले 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। एसपी अनुराग वत्स ने पत्रकारों को बताया कि बच्चों के अगवा होने की सूचना बाद से पुलिस लगातार सक्रिय रही। पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस करके सटीक स्थान पर दबिश दी। रात करीब दो बजे पुलिस उस स्थान पर पहुंची। तब तक बदमाश एक बच्चे श्रेयांश उम्र 6 वर्ष की हत्या कर चुके थे। दूसरे के सर भी गंभीर चोंट मार चुके थे। पर, उसे टीम ने जिन्दा बरामद कर जिला अस्पताल ले आई। जहां से ट्राम सेंटर भेजा गया।

क्या है मामला:

गोशाईगंज थाने के महिलो आशापुर निवासी राकेश कुमार अग्रहरि के बेटे दिव्यांश 08 और श्रेयांश 06 का बदमाशों ने सरस्वती विद्या मंदिर कटका खानपुर में स्कूल में छुट्टी होने के बाद गेट से ही गुरुवार को पौने 12 बजे अपहरण कर लिया था। बदमाशों ने अगवा सगे भाइयों के पिता को उनके मोबाइल पर फोन कर 50 लाख रुपए फिरौती मांगी थी। मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण हड़बड़ाए नौसिखिया बदमाशों ने श्रेयांश की हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने शुक्रवार को एसपी ने पत्रकारों को बताया कि गोशाईगंज थाने की पुलिस और स्वाट टीम ने कोतवाली नगर के करौंदिया मोहल्ले के एक मकान से दबिश के दौरान रात करीब दो बजे तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान सूरज बहेलिया पुत्र घनश्याम हरिओम उर्फ शिवनन्दन शर्मा पुत्र श्रवण कुमार निवासी पलिया और रघुवर यादव पुत्र रामजी निवासी कोहड़ा के रूप में की गई है। पुलिस ने यहां से श्रेयांश के शव को बोरे से बरामद किया। उसका भाई दिव्यांश घायल मिला। पुलिस ने फरार बदमाश शिवपूजन राय पुत्र संतोष निवासी कोहड़ा थाना गोशाईगंज को कोतवाली देहात थाने के अभियाकला शम्भूगंज रोड पर मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। एसपी ने बताया कि राकेश के यहां रघुवर नौकरी करता था। उसी ने पूरी घटना का प्लान किया। घायल दिव्यांश और बदमाश का लखनऊ के अस्पताल में इलाज चल रहा है।

गे पार्टनर के साथ रहने के लिए किया पत्नी का कत्ल, मोबाइल से खुला रहस्य

नई दिल्ली एजेंसी। एक सनसनीखेज घटना में भारतीय मूल की महिला को उसके गे पति ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह अपने ब्वॉयफ्रेंड (पुरुष पार्टनर) के साथ भागकर ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहता था। मिहिला की पहचान जेसिका पटेल के रूप में हुई है। वह अपने पति मितेश के साथ उत्तरी इंग्लैंड के मिडिल्सबोरो में रहती थी।

37 साल का मितेश पटेल जोकि एक गे था उसे अपनी फार्मासिस्ट पत्नी जेसिका पटेल की हत्या का दोषी पाया गया। मितेश पटेल पहले पत्नी की हत्या से इनकार करता रहा लेकिन पुलिस ने जब दोनों के मोबाइल फोन की पड़ताल की तो घटना की सच्चाई परत दर परत खुलने लगी।

इसी दिसंबर माह में स्थानीय अदालत ने मितेश पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जज ने मामले की सुनवाई में पाया कि आरोपी मितेश ने सुपरमार्केट के प्लास्टिक बैग से जेसिका दम घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी जिससे कि वह अपने पुरुष पार्टनर के साथ रह सके। लेकिन मितेश ने जिस तरह से हत्या की साजिश रची और घटना को अंजाम दिया वह हैरान करने वाला है। आगे पढ़ें कैसे की पत्नी जेसिका की हत्या-

हैरान करने वाली मर्डर की ये कहानी

पुलिस जांच के अनुसार मितेश ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले अपने गे पार्टनर से डेटिंग एप ग्रिंडर के जरिए मिला था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने तो मितेश पूरे दिल से उसे अपना जीवन साथी मान चुका था। इसके बाद वह 2015 में अपनी पत्नी की हत्या का प्लान बनाने लगा था। पत्नी की हत्या करनी है इसके लिए उसने उसका 2 मिलियन ब्रिटिश पाउंड यानी करीब 18 करोड़ रुपए का जीवन बीमा भी कराया।

इसके साथ ही वह गूगल में पत्नी की हत्या के लिए सर्च भी करता था जैसे इधर जब जेसिका यह बात पता चल चुकी थी कि उसका पति गे है और उससे बच्चा होना संभव नहीं है तो वह डॉक्टरों की सलाह से आईवीएफ तकनीक के जरिए बच्चा पाने की आशाएं सहेज रही थी। लेकिन मीतेश के दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने इंसुलिन का एक इंजेक्शन लाया और मौका पाते ही जेसिका को लगा दिया।

इस दौरान जेसिक छटपटाई और बचने की कोशिश की। इंजेक्शन लगने के कुछ देर बात वह इंजेक्शन के असर में जमीन पर गिर गई तो मितेश प्लास्टिक बैग से उसका मुंह ढक दिया। जिससे कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।

मोबाइल फोन से खुला हत्या का रहस्य

इसके बाद मितेश घर का सामान बिखेर कर घटना को लूटपाट का रंग दिया और फिर पुलिस फोन किया उसकी पत्नी को किसी ने मार दिया है और घर में लूट पाट की गई है। पुलिस टीम ने तफ्शीस शुरू की तो डस्टबिन में जेसिका मोबाइल मिला। इसके बाद पुलिस ने मितेश का भी मोबाइल जब्त किया और डाटा एलालिसिस के जरिए जांच की तो शक की सुई मितेश की ओर गई। इसके बाद पुलिस ने मितेश को गिरफ्तार कर लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की तो घटना का सच सामने आ गया।

संपादकीय

नौजवानों की समस्याओं का हल

हाल में जो दस्तावेज इंडिया 75 पर जारी किया है, उसे देखकर साफ होता है कि नीति आयोग काफी महत्त्वाकांक्षी हो रहा है। हालांकि यह बात अलग है कि महत्त्वाकांक्षी होना जरूरी इसलिए है कि भारत के किसानों-नौजवानों की समस्याओं का हल एक हद तक उन महत्त्वाकांक्षी विकास दरों में ही निहित है। नीति आयोग का मानना है कि 2018 से 2023 तक विकास दर 8 प्रतिशत रहनी चाहिए। 8 प्रतिशत विकास बहुत ज्यादा तो नहीं है। 2017-18 की विकास दर करीब सात प्रतिशत रहने वाली है। इसे देखते हुए लगातार पांच वर्षो तक आठ प्रतिशत की विकास दर हासिल कर पाना खासा चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। नीति आयोग चाहता है कि भारत की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ यानी 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 4 ट्रिलियन डॉलर का हो जाए, अभी यह आकार दो ट्रिलियन डॉलर से कुछ ज्यादा का है। यानी नीति आयोग आगामी करीब चार सालों में भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को दोगुना करना चाहता है, यह आसान नहीं है। खासकर तब जबकि कृषि की बदहाली की खबरें लगातार आ रही हों। खेती के लिए इस दस्तावेज में उत्पादकता बढ़ाने के सुझाव हैं। दस्तावेज के मुताबिक वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की योजना होनी चाहिए। हर परिवार को पक्का घर होना चाहिए। 2019 तक चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध हो। आयोग का कहना है कि अर्थव्यवस्था में निवेश की दर बढ़ाई जाएगी। यह फिलहाल सकल घरेलू उत्पाद की 29 प्रतिशत है; इसे बढ़ाकर 36 प्रतिशत किया जायेगा। नीति आयोग ने कर-जीडीपी अनुपात को सुधारने की बात भी कही है। यानी बातें बहुत हैं और अच्छी बातें हैं। इस मुल्क में आजादी से लेकर अब तक कौन सी सरकार ऐसी है, जिसने खेती के विकास की बात न की है और आजादी के सत्तर सालों से ज्यादा बीतने के बावजूद अधिसंख्य किसानों की हालत यह है कि उनकी अर्थव्यवस्था वेंटीलेटर पर है। कर्जमाफी के बगैर किसानों के अस्तित्व पर खतरा है। नीति आयोग का यह मानना है कर्ज माफी खेती की समस्याओं का दीर्घकालीन हल नहीं है, पर जो भी हल है किसानों की समस्याओं का, उसे सामने लाए बगैर 75 वीं वर्षगांठ बहुत शानदार तरीके से नहीं मनाई जा सकती। किसानों की समस्याओं का राजनीतिक इस्तेमाल वह पार्टियां भी करने में नहीं चूकेंगी, जो खुद केंद्र और राज्य सरकारों में बरसों से सत्ता पर काबिज रही हैं।

एकजुट रहने की घोषणा

भारतीय राजनीति का भौंडापन देखना हो तो राजग में शामिल कुछ नेताओं के रवैये पर नजर डालना पर्याप्त है। उपेन्द्र कुशवाहा साढ़े चार वर्ष तक मंत्री बने रहे और अंत में उनको लगने लगा कि मोदी सरकार ने पिछड़ों और गरीबों के लिए कोई काम ही नहीं किया। एक दिन पहले तक राजग में एकजुट रहने की घोषणा करने वाले लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष चिराग पासवान को अब लगने लगा है कि राहुल गांधी में सकारात्मक बदलाव आया है। लोजपा की बिहार ईकाई ने 31 दिसम्बर तक सीटों पर समझौता अंतिम करने का अल्टीमेटम दे दिया है। भाजपा को राजग के साझेदारों की आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर में ही आवश्यकता है। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू पहले ही किनारा कर चुके हैं। बिहार में कुशवाहा ने अलग रास्ता बना लिया। लोजपा को लगा है कि भाजपा को दबाव में लाने का यही समय है। इसलिए उसने ऐसा बयान दिया है। वैसे भी बिहार में लोजपा के लिए राजद, कांग्रेस गठबंधन में आने का दरवाजा खुला हुआ है और विपक्ष की कोशिशें भी जारी हैं। शिवसेना लगातार भाजपा को कठघरे में खड़ा कर रही है। वह क्या करेगी कहना कठिन है। तो क्या राजग 2019 के पहले बिखर जाएगा? कुछ भी हो सकता है। हमारे देश के नेता कब पलटी मार देंगे कहना मुश्किल है। यहां विचार और सिद्धांत की जगह चुनाव में जीत-हार और सत्ता प्राप्ति की संभावना पार्टियों के बीच हाथ मिलाने का आधार बनता है। 2014 में नरेन्द्र मोदी की लहर में जिनको जीत और सत्ता दिख रही थी वे आए, उनको लाभ मिला। बिहार की स्थिति में मोदी के साथ कुशवाहा और पासवान नहीं होते तो आज उनकी राजनीतिक दशा वही होती तो उस समय राजद और जद यू की हुई। वैसे नीतीश कुमार के साथ आने पर कुशवाहा का बाहर जाना तय हो गया था। नीतीश और पासवान के लिए मंदिर निर्माण के लिए कानून या अध्यादेश स्वीकार करना कठिन होगा। वे ऐसा खुल कर जता चुके हैं। हो सकता है इसी मुद्दे पर राजग बिखर जाए। इसलिए राजग के भविष्य के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। आज कौन राजग में है कौन नहीं है, इससे बड़ा प्रश्न यह है कि जनवरी में यदि शीर्ष अदालत ने प्रतिदिन सुनवाई आरंभ नहीं की और भाजपा को अध्यादेश जारी करने का निर्णय करना पड़ा तो कौन रहेगा?

सीटों पर जीत हासिल

नरेन्द्र मोदी की आंधी में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिन दो सीटों पर जीत हासिल कर पाई, उनमें छिंदवाड़ा भी एक था। और फिर सिंधिया बनाम दिग्विजय की लड़ाई के चलते ``बाहरी' कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई। कांग्रेस जीत भी गई और इसी लड़ाई ने बुजुर्ग कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवा दिया। युवा और साफछवि का होकर भी ज्योतिरादित्य मुंह ताकते रह गए। पर सत्ता संभालते ही कमलनाथ ने जो बयान दिया, वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेसियों के मुंह छुपाने का कारण बना ही, खुद कमलनाथ का भी सारा ``परिचय' सामने ला दिया। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी के साथ ही नौजवानों को रोजगार लायक बनाने की बात कहते-कहते यह भी कह दिया कि मध्य प्रदेश की नौकरियों पर बिहार-यूपी के लोग कब्जा कर लेते हैं। सो उन्होंने उद्योगों को तभी इंसेंटिव देने की घोषणा।

सतीश पेडणोकर

प्रदेश के नये मुख्यमंत्री कमलनाथ किस प्रदेश और बिरादरी से हैं, यह उनके लम्बे राजनैतिक कॅरियर के बावजूद बहुत लोगों को पता नहीं था। उनकी संजय गांधी से भी कैसी और कितनी दोस्ती थी, इसका भी खास जिक्र नहीं मिलता, पर कांग्रेस ने जब 1980 के आम चुनाव में हिन्दी पट्टी की सबसे सुरक्षित छिंदवाड़ा सीट (जिस अकेली सीट से 1977 में कांग्रेस जीती थी) इस बाहरी उम्मीदवार को दी, तब उसका कारण यही गुण बताया गया। वे व्यवसायी हैं, पैसे वाले हैं, एक बड़े प्रबंधन कॉलेज के मालिक हैं। जैसे परिचय के साथ धीरे-धीरे यह ख्याति भी जुड़ती गई कि वे छिंदवाड़ा को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं। कालांतर जब कांग्रेस के अन्दर उनका कद बढ़ा और वे मंत्री बने तब भी यह चर्चा रही कि वे अपने विभाग के कामकाज कुशलता से निपटाते हैं। नरेन्द्र मोदी की आंधी में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिन दो सीटों पर जीत हासिल कर पाई, उनमें छिंदवाड़ा भी एक था। और फिर सिंधिया बनाम दिग्विजय की लड़ाई के चलते ``बाहरी' कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई। कांग्रेस जीत भी गई और इसी लड़ाई ने बुजुर्ग कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवा दिया।

युवा और साफछवि का होकर भी ज्योतिरादित्य मुंह ताकते रह गए। पर सत्ता संभालते ही कमलनाथ ने जो बयान दिया, वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेसियों के मुंह छुपाने का कारण बना ही, खुद कमलनाथ का भी सारा ``परिचय' सामने ला दिया। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी के साथ ही नौजवानों को रोजगार लायक बनाने की बात कहते-कहते यह भी कह दिया कि मध्य प्रदेश की नौकरियों पर बिहार-यूपी के लोग कब्जा कर लेते हैं। सो उन्होंने उद्योगों को तभी इंसेंटिव देने की घोषणा की जब वे सत्तर फीसद रोजगार स्थानीय लोगों को देंगे। अब इस दूसरी वाली घोषणा की भी आलोचना हो रही है पर बात यहां तक रहती तो कोई हर्ज न था। आखिर रोजगार के अवसरों पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का फैसला कई जगह चल रहा है और यह मांग स्थानीय बेरोजगारों की तरफ से उठती भी रही है। पर जैसे ही नाम लेकर बाहरी लोगों को निशाना बनाया गया राजनैतिक बवाल उठना स्वाभाविक है।

उत्तर प्रदेश और बिहार का आर्थिक हाल किसी से छुपा नहीं है। और अगर इन राज्यों के नौजवान और मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं तो इसका कारण उनकी अपनी बदहाली है। सो यह बयान राजनैतिक रूप से गलत होने के साथ ही असंवेदनशीलता का प्रमाण भी मान लिया गया। इस पर प्रतिक्रिया देने से राहुल भी बचते दिखे। कुछ समय पहले गुजरात से पुरबिया मजदूरों को, जिनमें मध्य प्रदेश के लोग भी थे, भगाया जा रहा था, तब वे विरोध में आगे थे। जब एमएनएस ने महाराष्ट्र से पुरबिया लोगों को पीटकर भगाना शुरू किया तो राहुल ने मुंबई जाकर विरोध किया था। इस बार कमलनाथ ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। कमलनाथ का वास्ता खेती से कम है वरना उनको मालूम होता कि आज मध्य प्रदेश गेहूं और सोयाबीन समेत कई फसलों के उत्पादन में तेजी से अगुआ बना है तो इसका कारण बाहरी कुशल मजदूर भी हैं और स्थानीय बनाम बाहरी का सवाल हर जगह रहता है पर मध्य प्रदेश में अब तक ऐसी कोई बात सुनाई नहीं देती थी। हम सब जानते हैं कि असम को खेती और बागान लायक बनाने, पंजाब को धान उगाना बताने से लेकर हर तरह के काम से आगे करने और मुम्बई (कोलकाता को जमाने तक) को देश की आर्थिक राजधानी बनाए रखने में अप्रवासी मजदूरों की क्या भूमिका रही है, यह बताने की जरूरत नहीं है। पर स्थानीयता का सवाल तो रहता है, भले उसकी आड़ में राजनीतिक लाभ लेने वाले दंगा भड़काने की सोचते हैं और राज ठाकरे जैसों की तो पूरी राजनीति इसी सवाल पर चलती है। असम में भी यह सवाल बड़ा बना तो राजनीति के चलते। गुजरात समेत कई राज्यों में 70-80 फीसद स्थानीय और बीस-तीस फीसद बाहरी का कानून है। और इस बार के दंगों में यह सवाल उठा कि कई मालिक फायदे के लिए इसका पालन नहीं करते या ठेके की मजदूरी के सहारे इस प्रावधान का उल्लंघन करते हैं। इस कानून पर जरूर अमल होना चाहिए। पर इनसे भी बड़े सवाल हैं, जिनको इस अवसर पर उठाना चाहिए और उनकी चर्चा होनी चाहिए। असमान क्षेत्रीय विकास और व्यक्तियों के साथ-साथ राज्यों के बीच भी तेजी से बढ़ती असमानता भी हमारी अर्थव्यवस्था और राजनैतिक चर्चा का मुद्दा बनना चाहिए।

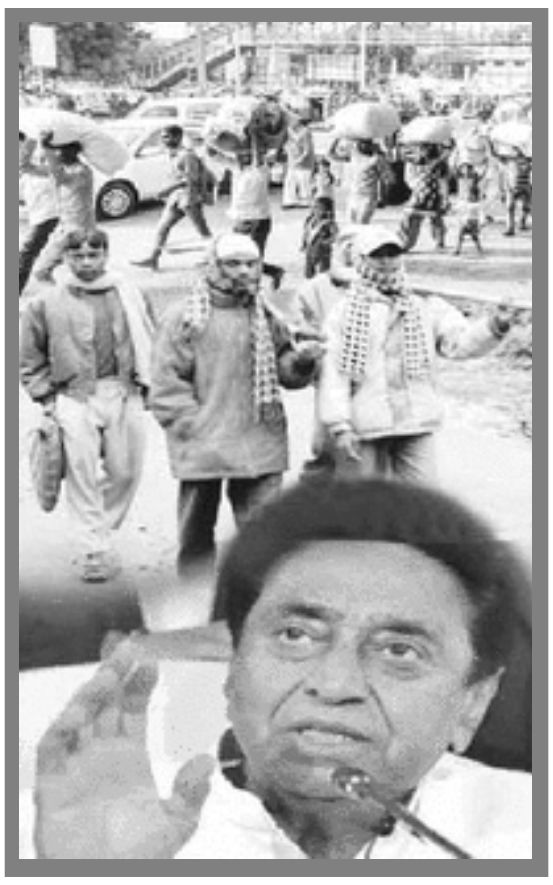

जब से नीतीश कुमार बिहार के अगुआ बने हैं, बिहार लगातार रिकार्ड दर से अपना जीडीपी बढ़ाए जा रहा है। सब ताली पीटते हैं पर कोई नहीं पूछता कि यह विकास कहां तक पहुंचा? बिहार राज्यवार विकास की सूची में अंतिम पायदान पर बना ही हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या पूरा हिन्दी इलाका उसी गति को प्राप्त है। दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों को छोड़कर पूरी हिन्दी पट्टी उद्योगों से वीरान हो गई है। कानपुर तक डूब गया, बिहार के रोहतास इलाके के उद्योग तो कब के समाप्त हो गए? पलायन छोड़कर बिहार की कोई आमदनी नहीं है-सुशासन के बावजूद कोई नया उद्योग, कोई नया कारोबार नहीं शुरू हुआ है। खेती सुधरी है तो लोगों के अपने दम से..। और इस बार का मसला यह है कि किसी गैर-हिन्दी वाले प्रदेश ने और किसी टुटपूंजिया समूह ने यह मसला नहीं उठाया है। एक मुख्यमंत्री ने और वह भी हिन्दी पट्टी के ही एक बीमारू माने जाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही मसला उठाया है। जब मजदूर बिना पढ़े-लिखे या तकनीकी ज्ञान के अपने से उन्नत इलाके के श्रम बाजार में पहुंचता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है, उसे अनजान इलाके की बोली, खान-पान, नरक जैसे रहने वाले हालात में क्या-क्या भुगतना पड़ता है, उसके परिवार की औरतों को कितने बलात्कार झेलने पड़ते हैं, इसकी गिनती उन लोगों के पास नहीं होती, जो एक अपराधी मानसिकता के मजदूर के अपराध के चलते पूरे हिन्दीभाषी मजदूरों को निशाना बनाने से बाज नहीं आते। प्रवासी मजदूर किसी भी मालिक के दुलारे नहीं होते-वे सस्ता श्रम करने, सौदेबाजी की हालत में न रहने, लाल झंडा देखकर भागने और श्रम नियमों को आसानी से भुलाने के चलते मालिकों के प्रिय होते हैं। विकास के सारे मानकों पर पीछे आकर घर छोड़ने को मजबूर ये लोग किस तरह श्रमिक आंदोलन की सारी उपलब्धियों पर पानी फेरते हैं; ये नहीं जानते और कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टियां कब उन्हें अपनी राजनीति में इस्तेमाल करती हैं, इसका भी उन्हें पता नहीं होता।

चलते चलते

``अतिरिक्त सहूलियतों'

जब आम आदमी भू माफिया के चंगुल में फंसता होगा तो उसकी क्या दशा होती होगी? आज जब छोटे शहरों में जमीन की कीमत करोड़ों छू रही है, ऐसे में मुंबई के क्या कहने? सोना उगलने वाली जमीन के धंधे में ईमानदार भी आए तो बेईमान और दबंगों ने भी हाथ आजमाया। लिहाजा जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े विवाद तेजी से बढ़े।

चलित धारणा है कि हस्तियां अतिरिक्त सहूलियतों से लैस होती हैं, उन्हें अपने ``काम' के लिए आम लोगों की तरह मगजमारी नहीं करनी पड़ती। अक्सर इन ``अतिरिक्त सहूलियतों' के लिए इनकी आलोचना भी होती है। मगर कई बार कुछ हस्तियां भी रसूख रखने के बावजूद व्यवस्था से निराश और बेबस हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही मामला ``अभिनय के संस्थान' दिलीप कुमार का सामने आया है। इनको अपना घर बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक को पत्र लिखना पड़ा। मामला दिलीप कुमार के घर को भू माफिया द्वारा कब्जाने की कोशिश का है। दिलीप कुमार की अभिनेत्री पत्नी सायरा बानो के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कई बार इस संदर्भ में फरियाद करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अपने आशियाने को बचाने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री तक यह बात पहुंचानी पड़ी। इस साल की शुरुआत में सायरा बानो ने भूमाफिया समीर भोजवानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। यह उदाहरण है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भू माफिया के रसूख और दबदबे का, जिसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत न तो क्षेत्र के थानेदार की है न राज्य के ``थानेदार' की जबकि मामला पूरे देश में सुर्खियों में है। इसके बावजूद कार्रवाई न होना, क्या जताता है! इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आम आदमी भू माफिया के चंगुल में फंसता होगा तो उसकी क्या दशा होती होगी? आज जब छोटे शहरों में जमीन की कीमत करोड़ों छू रही है, ऐसे में मुंबई के क्या कहने? सोना उगलने वाली जमीन के धंधे में ईमानदार भी आए तो बेईमान और दबंगों ने भी हाथ आजमाया। लिहाजा जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े विवाद तेजी से बढ़े।

आज पूरे देश में पुलिस-प्रशासन के ``सहयोग' और नेताओं के ``आशीर्वाद' से जमीन कब्जाने का ``उद्योग' खूब फल-फूल रहा है। दिलीप कुमार के बहानेही सही, सरकार को इस ``उद्योग' पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। बिल्डरों और माफिया को उनके ``आशियाने' में पहुंचाना ही कानून के इकबाल की तसदीक करेगा।

``संतुलित और समावेशी'

पोलैंड में आयोजित जलवायु बदलाव पर सम्मेलन के जो परिणाम निकले हैं, उन्होंने इस अति महत्त्वपूर्ण मुद्दे की प्रक्रिया को जीवित जरूर रखा है, पर इससे समय रहते समस्या के समाधान की उम्मीद वास्तव में पूरी नहीं हुई है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए कहीं अधिक मजबूत उपलब्धि की जरूरत थी। भारत में केरल जैसी गंभीर बाढ़ हो या अमेरिका के वनों में सभी सीमाओं को पार करती आग, अनेक अति विनाशकारी आपदाओं के तार जलवायु बदलाव के व्यापक संकट से जोड़े जा रहे हैं। इनसे भी ज्यादा गंभीर आपदाओं विशेषकर समुद्र स्तर के अाकि ऊपर उठने की चेतावनियां वैज्ञानिक दे रहे हैं। तिस पर विशेषज्ञों को यह भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में उपेक्षित कमी नहीं आ रही है, अपितु इसमें तो पिछले रिकार्ड तोड़ने वाली अधिकता आ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 22 नवम्बर 2018 को जारी आंकड़ों में बताया कि कार्बन डाइऑक्साईड का स्तर 2017 में पिछले वर्ष की अपेक्षा और बढ़ गया। वर्ष 1750 के आसपास को औद्योगीकरण-पूर्व का समय माना जाता है। इसकी तुलना में वर्ष 2017 तक कार्बन डाइऑक्साईड उत्सर्जन 46 प्रतिशत बढ़ा है। सबसे आर्श्चय व खेद की बात यह है कि इसमें से अधी वृद्धि 1750-1987 के बीच हुई व शेष आधी वृद्धि 1987-2017 के बीच हुई। यानी जो वृद्धि औद्योगीकरण के 237 वर्षो में हुई थी, लगभग उतनी ही वृद्धि इसके बाद के 30 वर्षो में हो गई। यह 30 वर्ष ही वह समय था जब मनुष्य को पता चल चुका था कि जलवायु बदलाव की समस्या कितनी गंभीर है। यह जानकारी मिलने के बाद भी तीन दशक में कार्बन डाइऑक्साईड के स्तर में इतनी वृद्धि होने दी गई जितनी कि पिछले 237 वर्षो में हुई थी। इन तीन दशकों में जलवायु बदलाव पर कितनी ही बड़ी अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस हुई। जलवायु बदलाव अंतरसरकारी मंच (आई.पी.सी.सी.) का गठन हुआ व इसकी ऐसी अनेक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिनसे समस्या की बढ़ती गंभीरता का पता चलता है। अनेक स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने भी ऐसी चेतावनियां जारी कीं व इस वर्ष अक्टूबर में तो वैज्ञानिक लंदन में अपनी चेतावनियों को लेकर सड़क पर भी आ गए हैं। वैज्ञानिक पहले तापमान वृद्धि को 20 सेल्सियस तक सीमित करना जरूरी मानते थे पर फिर अधिक सहमति इस पर बनी कि बड़ी आपदाओं को रोकने के लिए यह वृद्धि 1.50 सेल्सियस तक ही सीमित करनी चाहिए। पर कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन में जो प्रवृत्तियां इस समय मौजूद हैं वे तो इस सीमा से कहीं आगे पहुंचने का संकेत दे रही हैं। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वर्ष 2020 तक के जो उत्सर्जन के अनुमान प्रस्तुत किए वह 21 वीं शताब्दी में तापमान वृद्धि 20 सेंटीग्रेट तक रोकने के अनुकूल नहीं है, अपितु 21 वीं शताब्दी के अंत तक 2.50 सेंटीग्रेट से 50 सेंटीग्रेट तक की वृद्धि का संकेत देते हैं। वर्ष 2015 में जलवायु बदलाव व स्वास्य पर लैंसेट आयोग ने बताया कि शताब्दी के अंत तक की संभावनाएं 2.60 सेंटीग्रेट 4.80 सेंटीग्रेट तक की तापमान वृद्धि की हैं। अमेरिका की देखादेखी अन्य महत्त्वपूर्ण देश भी पीछे हट रहे हैं। जिस पर आमजन को आगे आना होगा। आगामी दिनों में जलवायु बदलाव के संकट के समाधान के लिए एक बहुत व्यापक जन-अभियान चलाना होगा। इसके बिना केवल अंतरराष्ट्रीय संस्थागत प्रयासों से बात बन नहीं रही है, और न ही राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारों के प्रयास पर्याप्त हैं।

सत्संग

याद

कर्म क्या है? आप जिस तरह किसी बात को ग्रहण करते हैं, उसे जानते हैं, उसे अनुभव करते हैं और जिस तरह किसी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, वह आपके अतीत की यादों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप शांतिदायक संगीत सुनना चाहते हैं और हम आपके लिए बहुत तेज आवाज में बीट्स वाले गाने चला दें तो आपकी नसें फट जाएंगी, लेकिन वहीं कुछ ऐसे नौजवान होंगे, जिन्हें यह पसंद आएगा। एक ही आवाज किसी एक इंसान के कानों को संगीत लगती है तो किसी दूसरे को शोर लगता है। आप किसी खास आवाज को कैसे लेते हैं, ये आपके कर्म हैं। इसलिए हमने कहा था कि जब हम कर्म की बात करते हैं तो हमारा मतलब आपके कष्ट भोगने से नहीं होता है। यह कर्म का पक्ष नहीं है। कर्म का अर्थ होता है गतिविधि। इस वक्त यहां बैठे हुए हमारी गतिविधि चार आयामों में हो रही है-भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा के स्तर पर। आज आपके जागने के पल से इस पल तक इन चारों कर्मों में से कितनों के प्रति आप जागरूक रहे हैं? आप नहीं गिन पा रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि यह एक प्रतिशत से भी कम होगा। जब आप अपने कर्मो के केवल एक प्रतिशत के प्रति ही सचेत रहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जिंदगी में सब कुछ संयोग से हो रहा होता है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं और एक प्रतिशत समय के लिए ही आंखें खुली रखते हैं, बाकी समय आंखों को बंद करके गाड़ी चलाते हैं, फिर दुर्घटना तो होनी ही है। यही जीवन में हो रहा है और इसीलिए इतना ज्यादा तनाव, इतना ज्यादा डर है क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर चीजें अचेतन में हो रही हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपका शरीर क्या कर रहा है, आपकी ऊर्जा, आपके विचार, आपकी भावनाएं क्या कर रही हैं, इन सब बातों के प्रति केवल मुट्ठी भर लोग ही जागरूक हैं। अगर आप चेतना का दायरा बढ़ा लेते हैं तो अचानक आपको महसूस होने लगता है कि सबकुछ आपके अपने हाथ में है। अगर आप अपनी सोचने की शक्ति पर काबू पा लेते हैं तो चालीस से पचास प्रतिशत भाग्य और जिंदगी आपके हाथों में होगी और अगर इसके साथ भावना भी जुड़ जाए तो समझिए कि दोनों का चालीस से सत्तर प्रतिशत भाग आपने काबू में कर लिया।

फोटोग्राफी...

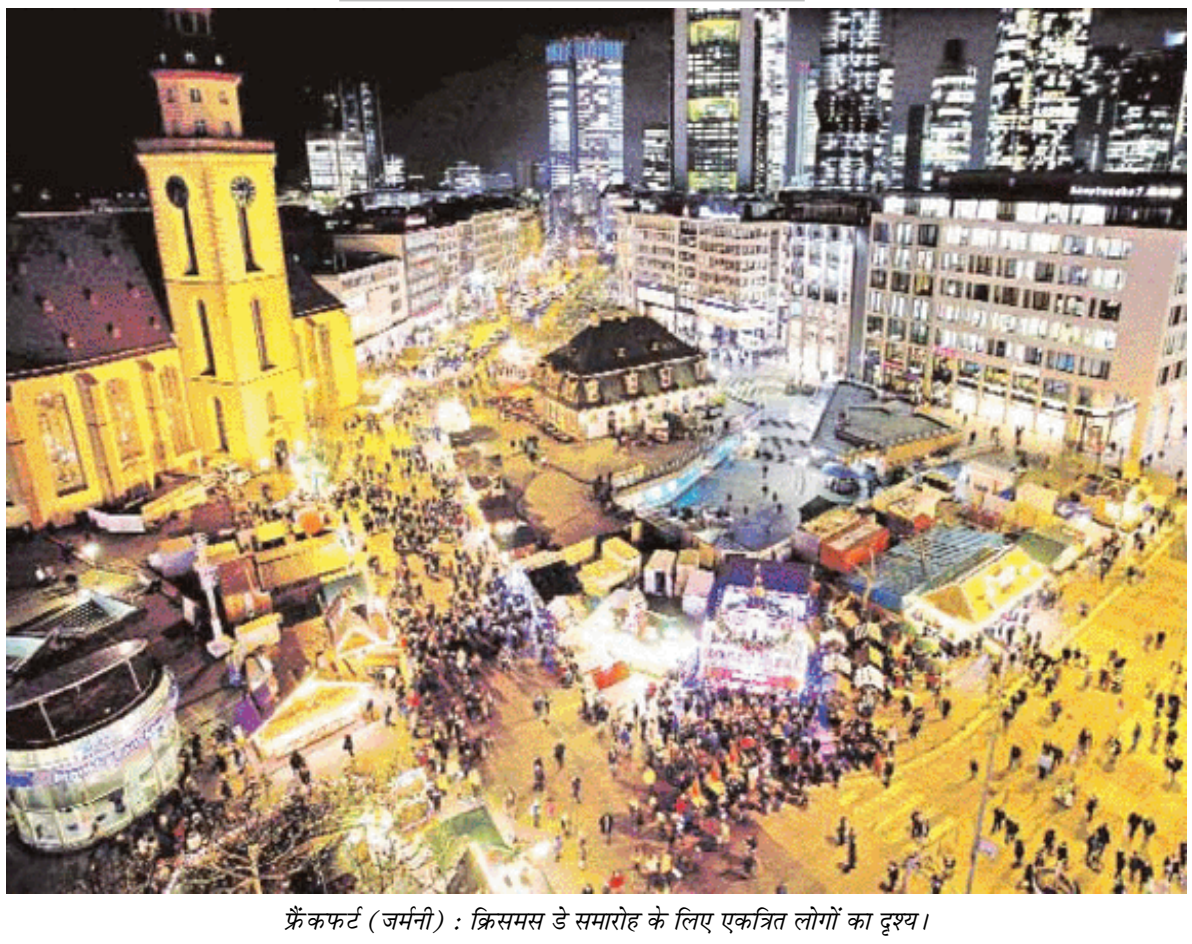

फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) : क्रिसमस डे समारोह के लिए एकत्रित लोगों का दृश्य।

सार समाचार

चेक गणराज्य में खदान दुर्घटना में 13 खनिकों की मौत, 10 घायल

प्राग । चेक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में एक खदान में मीथेन गैस के दहन से 13 खनिकों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए. एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. ओकेडी खनन कंपनी के प्रवक्ता इवो सेलेचोवस्की ने बताया, ''कुल 13 खनिकों की मौत हुई है. इनमें 11 खनिक पोलैंड के और चेक गणराज्य के दो खनिक हैं.'' दुर्घटना गुरुवार दोपहर कार्विना शहर में सीएसएम खदान में हुई. यह खदान पूर्वी प्राग से करीब 300 किलोमीटर (200 मील) की दूरी पर है. बात दें ऐसा ही एक हादसा चीन के चानदोंग प्रांत में 20 अक्टूबर को हुआ था. वहां रात को एक कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में दो मजदूरों की मौत हो गई थी. साथ ही 20 अन्य मजदूर खदान में फंस गए थे. सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया था कि यह कोयला खदान युनचेंग काउंटी में है. विस्फोट के बाद 22 कर्मी बाहर नहीं निकल पाये थे. इस कोयला खदान की मालिकाना हक की कंपनी चानदोंग एनर्जी ग्रुप कंपनी लिमिटेड के विशेषज्ञ झाई मिंगहुआ ने बताया कि घटना के समय खदान में 334 लोग काम कर रहे थे. इनमें से 312 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था.

फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 'येलो वेस्ट' कर कटौती को दी मंजूरी

पेरिस: फ्रांस की नेशनल असेंबली ने शुक्रवार को करों में आपात कटौती से जुड़े पैकेज को मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने 'येलो वेस्ट' प्रदर्शनों को खत्म करने के लिये इस महीने की शुरुआत में कम वेतन वाले लोगों के लिये करों में कटौती का एलान किया था. शुक्रवार सुबह शुरुआती घंटों तक चली बहस के दौरान श्रम मंत्री म्यूरिएल पेनीकॉड ने कहा कि इस संकट को खत्म करने के लिये यह कदम काफी महत्वपूर्ण साबित होगा.

करों में कटौती से बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों और ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों को भी फायदा होगा. अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि इससे फ्रांस की सरकार पर 15 अरब यूरो (17 अरब अमेरिकी डालर) का बोझ पड़ेगा. अब इस प्रस्ताव को सीनेट की मंजूरी के लिये भेजा जाएगा. गौरतलब है कि फ्रांस में पिछले महीने से ईंधन करों में वृद्धि के खिलाफ 'येलो वेस्ट' नाम से जारी प्रदर्शनों में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है.

चीन के जजों ने किया मौत की सजा का बचाव, कहा- इसे खत्म करना आसान नहीं

बीजिंग। चीन के सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष जजों ने मौत की सजा का बचाव किया है। उनका कहना है कि जीवन के बदले जीवन लेने की भावना लोगों के मन में सदियों से समाई है, इसलिए देश में मौत की सजा को समाप्त करना आसान नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बीते मंगलवार को आरोप लगाया था कि वैश्विक मानदंडों के विपरीत चीन में मौत की सजा दुर्लभ मामलों के बजाय साधारण अपराधों में भी दी जा रही है। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप शीर्ष कोर्ट की जज ली जिओ ने गुरुवार को कहा, 'मौत की सजा के मामलों को घटाने के प्रयास के बावजूद हम इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि इसे जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है। मौत की सजा खत्म करने से जनता में रोष बढ़ सकता है। हजारों वर्षो से जीवन के बदले जीवन लेने की भावना लोगों के मन में बसी है। अगर मौत की सजा के आंकड़े जारी किए जाएं तो लोग कहेंगे कि कुछ और को यह सजा होनी चाहिए थी।' अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, चीन में हर साल करीब दो हजार लोगों को फांसी दी जाती है। चीन हालांकि मौत की सजा के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करता।

अफगानिस्तान का सबसे भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदार है भारतः पेंटागन

वाशिंगटन (एजेंसी)।

पेंटागन ने युद्धप्रभावित अफगानिस्तान के शांतिपूर्ण विकास में भारत के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारत अफगानिस्तान का सबसे भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदार है। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में पेश जून से नवंबर तक की अर्द्धवार्षिक अफगान रिपोर्ट में कहा कि भारत ने अमेरिका की नयी दक्षिण एशिया नीति आने के बाद अफगानिस्तान में अपनी आर्थिक भागीदारी बढ़ायी है।

पेंटागन ने रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2017 में दक्षिण एशिया रणनीति की घोषणा की थी। इस नीति में पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव बनाने पर जोर दिया गया है कि वह छद्म आतंकवादी और आतंकवादी समूहों के लिए समर्थन और सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने पर रोक लगाये और अफगान सुलह समझौते में एक रचनात्मक भूमिका निभाये।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अमेरिकी रणनीति में दक्षिण एशिया में स्थिरता बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय रूख का आह्वान किया गया है। इसमें एक स्थिर अफगानिस्तान के लिए आमसहमति बनाना, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और सहयोग पर जोर देना, अफगान नीत शांति प्रक्रिया के लिए सहयोग पर जोर देना तथा देशों को छद्म ताकतों के इस्तेमाल के लिए जवाबदेह बनाना जिससे स्थिरता और क्षेत्रीय भरोसा कमजोर होता है।

पेंटागन ने कहा, ''भारत अफगानिस्तान का सबसे भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदार और क्षेत्र में विकास में सहायता देने वाला सबसे बड़ा सहयोगकर्ता है।''। भारत ने 2015 के अंत से विकास में सहायता के तौर पर एक अरब डालर का वादा किया है। इसके अलावा भारत अफगान के आधारभूत ढांचे पर दो अरब डालर पहले ही खर्च कर चुका है।

इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से की फोन पर बातचीत, उठाया कश्मीर मुद्दा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस से अपील की कि कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों का संज्ञान लें। डॉन ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान के हवाले से खबर दी है कि गुतारेस से टेलीफोन पर हुई बातचीत में खान ने इन उल्लंघनों को खत्म किए जाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को चिह्नित किया।

कश्मीर के पुलवामा में सात नागरिकों की हत्या की निंदा करने और मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की चेतावनी देने के कुछ दिनों बाद खान ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को फोन किया। इससे अलग संघीय कैबिनेट ने अपनी बैठक में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की निंदा की। सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि कैबिनेट की बैठक इस्लामाबाद में हुई जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री खान ने की।

सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का अफगान सुरक्षा पर नहीं पड़ेगा असर

काबुल (एजेंसी)।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि उनके देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से इस युद्ध ग्रस्त देश की सुरक्षा पर असर नहीं पड़ेगा।

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की खबर के बीच यह पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आयी है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता हारून चखानसूरी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है, ''अगर वे अफगानिस्तान से जाएंगे, तो इससे सुरक्षा पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पिछले साढ़े चार साल में अफगानों का पूरा नियंत्रण हो गया है।''

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का

कहना है कि सीरिया में वर्षों से आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रही अमेरिकी सेना को अब घर वापस बुलाने का वक्त आ गया है। बुधवार को ट्विटर पर पोस्ट एक वीडियो संदेश में आईएस जिहादियों की हार की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा, ''हम जीत गए।'' उन्होंने कहा, ''हमने उन्हें हरा दिया है और उन्हें बुरी तरह हराया है। हमने जमीन वापस ले ली है। उन्होंने कहा, ''इसलिए हमारे लड़के, युवतियां, हमारे लोग.... वे सभी वापस आ रहे हैं।'' वाशिंगटन में सीरिया से 2000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की खबरों के बीच ट्रंप का यह संदेश आया है। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने इस पर अंतिम फैसला मंगलवार को लिया। वहीं, व्हाइट हाउस का कहना है कि सीरिया से सैनिकों को वापस बुलाने का ट्रंप का फैसला उनकी नीतियों के अनुरूप है क्योंकि युद्ध से जर्जर देश में अमेरिकी सैनिकों का मुख्य कार्य आईएस को हराना था। अमेरिकी सेना वहां कभी भी गृहयुद्ध के समाधान के लिए नहीं गई थी।

पश्चिम लगातार शक्तिशाली हो रहे रूस से भयभीत है: व्लादिमीर पुतिन

मॉस्को (एजेंसी)।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम लगातार शक्तिशाली हो रहे रूस से भयभीत है साथ ही उन्होंने आर्थिक वृद्धि को और आगे बढ़ाने का वादा किया। पुतिन वर्ष के अंत में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। घरेलू स्तर पर बढ़ते असंतोष तथा यूक्रेन के साथ बढ़ते विवाद के कारण अमेरिका से बिगड़ते संबंधों के बीच यह वार्षिक कार्यक्रम हुआ है। रूस के खिलाफ पश्चिमी

प्रतिबंधों के बारे में पूछे जाने पर पुतिन ने कहा कि यह रूस की बढ़ती शक्तियों से जुड़ा है। पुतिने ने सैकड़ों पत्रकारों से कहा, ''एक शक्तिशाली खिलाड़ी सामने आता है उसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। अभी हाल तक ऐसा माना जाता था कि ऐसा कोई देश नहीं है।'' इस दौरान उन्होंने जासूसी के मामलों से इनकार किया। इनमें पूर्व डबल एजेंट सर्गेई स्क्रीपल और उसकी बेटी को इंग्लैंड में जहर देने का मामला शामिल है। पुतिन ने कहा, ''अगर स्क्रीपल नहीं होते तो उन्होंने कुछ और गढ़ लिया होता।'' पुतिन ने प्रश्नोत्तर के बड़े सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीरिया से सैनिकों को हटाने के निर्णय की सराहना की लेकिन शीत युद्ध के हथियार समझौते से हटने के मामले में उनकी आलोचना की।

खशोगी हत्याकांड के बाद खुफिया निगरानी बढ़ाने की कोशिश में सऊदी अरब

रियाद (एजेंसी)।

सऊदी शासन की आलोचना करने वाले पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न नाराजगी के मद्देनजर, सऊदी अरब ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अपने खुफिया अभियानों की निगरानी को बढ़ाने के लिए सरकारी निकायों का गठन कर रहा है. सऊदी शासन ने कहा कि तत्कालीन उप खुफिया प्रमुख अहमद अल-असिरी और शाही दरबार के सलाहकार सऊद अल-कहतानी के नेतृत्व में एक 'कपटपूर्ण अभियान' के तहत 2 अक्टूबर को इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास के भीतर खशोगी की हत्या कर दी गई थी. उन दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है.

सऊदी अरब के शाह सलमान ने बाद में अपने बेटे व क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की देखरेख में मुख्य खुफिया एजेंसी के पुनर्गठन का आदेश दिया, जिन्हें पत्रकार की हत्या को लेकर

वैश्विक स्तर पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन सऊदी सरकार लगातार इस बात से इनकार करती रही है कि वह उस गतिविधि में शामिल थे. आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी ने बृहस्पतिवार को कहा कि क्राउन प्रिंस की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और 'अनुमोदित प्रक्रियाओं' के अनुरूप खुफिया अभियानों के संचालन सुनिश्चित करने के लिए तीन विभागों के गठन को मंजूरी दी है.

चीन ने साइबर हैकिंग के आरोपों को नकारा, कहा- अमेरिका झूठ बोल रहा है

बीजिंग (एजेंसी)।

अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा चीन की सुरक्षा सेवा से जुड़े दो चीनी नागरिकों पर भारत समेत 12 देशों में साइबर जासूसी करने के आरोप तय करने के बाद चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर '' तथ्य गढ़ने'' का आरोप लगाया। आरोप के मुताबिक चीन के नागरिक झू हुआ और झांग शिलांग चीन में सक्रिय एक हैकिंग समूह के सदस्य हैं। साइबर सुरक्षा समुदाय में उस समूह को एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट कहा जाता है।

अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक वे दोनों चीन की हुआयिंग हैताइ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी के लिए और चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय तियानजिन स्टेट सिक्युरिटी ब्यूरो के साथ

मिलकर काम करते थे। वाशिंगटन ने कहा कि यह साइबर जासूसी का देश द्वारा प्रायोजित व्यापक अभियान था। चीन ने इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी और अमेरिका के साथ राजनयिक स्तर पर विरोध जताया।

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने एक वक्तव्य में कहा, ''अमेरिका के कदम से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों का गंभीर रूप से उल्लंघन होता है और यह दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है।'' हुआ ने कहा कि साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर चीन के खिलाफ लगाए अमेरिका के आरोप बेबुनियाद हैं।

अमेरिका और अन्य देशों की ओर से लगाए जाने वाले साइबर हमलों के आरोपों को चीन लंबे समय से नकारता आ रहा है। अमेरिका के सहयोगी ब्रिटेन ने भी चीन पर इन आरोपों का समर्थन किया है।

अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने ट्रंप के साथ मतभेद को लेकर इस्तीफा दिया

सियोल (एजेंसी)।

वाशिंगटन।अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने नीतिगत मामलों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतभेद को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, ट्रंप ने सेवाओं के लिए मैटिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह फरवरी में सम्मान के साथ सेवानिवृत्त होंगे। गौरतलब है कि मैटिस के पद से हटने की खबर सीरिया और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणाओं के बीच आयी है।

मैटिस ने गुरुवार को ट्रंप को भेजे गए इस्तीफे में लिखा है कि यह उनके लिए पद छोड़ने का ''सही वक्त'' है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ऐसा रक्षा मंत्री होना चाहिए ''जिसके विचार इन मामलों पर और अन्य विषयों पर भी आपसे बेहतर मेल खाते हों।''

उन्होंने लिखा है, ''मेरे कार्यकाल का अंतिम दिन 28 फरवरी, 2019 है। यह उत्तराधिकारी को नामित करने और उसकी नियुक्ति की पुष्टि करने के लिये पर्याप्त समय देगा। साथ ही सुनिश्चित करेगा कि मंत्रालय के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और आने वाले कार्यक्रमों जैसे संसदीय सुनवाई और फरवरी में होने वाली नाटो की रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक ठीक से हो।''

68 वर्षीय पेंटागन प्रमुख ने इसका जिक्र नहीं किया है कि वह खास तौर से सैनिकों को वापस बुलाने के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि, ट्रंप के इस फैसले से विभिन्न विदेशी सहयोगी और सांसद सभी दंग रह गए हैं। मैटिस का इस्तीफा मिलने के बाद ट्रंप ने फरवरी में उनके सेवानिवृत्त होने की घोषणा की।

राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, ''जनरल जिम मैटिस मेरे कार्यकाल में पिछले दो साल से रक्षा मंत्री के रूप में सेवाएं देने के बाद फरवरी के अंत में ससम्मान सेवानिवृत्त होंगे।'' उन्होंने लिखा है, ''जिम के कार्यकाल में बहुत प्रगति हुई है, खास तौर से नए खरीदी के संबंध में.....''।

गौरतलब है कि मैटिस भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के बड़े समर्थक हैं। सूचनाओं के अनुसार, सीरिया और अफगानिस्तान सहित विदेश नीति के विभिन्न मामलों पर मैटिस और ट्रंप के बीच मतभेद था।

मैटिस का नाम ट्रंप प्रशासन के उन वरिष्ठ अधिकारियों की लंबी सूची में जुड़ गया है जिन्हें पद छोड़ना पड़ा है या पद से हटा दिया गया है। ट्रंप ने ट्विटर पर घोषणा करके विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन को हटा दिया था। हालांकि, गुरुवार को ट्रंप ने कहा कि जल्दी ही नए रक्षा मंत्री की घोषणा की जाएगी।

बच्चों का उत्पीड़न करने वाले पादरियों को कानून के सामने करना चाहिए सरेंडर: पोप

वैटिकन सिटी, (एजेंसी)।

पोप फ्रांसिस ने शुक्रवार को संकल्प लिया कि कैथोलिक चर्च अब आगे से उत्पीड़न के आरोपों को हमेशा ''गंभीरता और तत्परता'' से लेगा. उन्होंने उत्पीड़न करने वालों से खुद को पुलिस के हवाले करने को कहा.

पोप ने वेटिकन में चर्च के प्रमुख संचालन समूह से सलाना संबोधन में कहा,'चर्च कभी चुप्पी साधने का प्रयास नहीं करेगा और हर मामले को गंभीरता से लेगा.' उन्होंने कहा,'यह स्पष्ट होना चाहिए कि इन आरोपों के संबंध में, चर्च इन अपराधों को अंजाम देने वालों को सजा देने के लिए जरूरी हरसंभव प्रयास करेगा.'

बाल यौन उत्पीड़न मामलों के कारण दुनिया भर में करीब सवा अरब अनुयायियों वाला रोमन कैथोलिक चर्च विवादों में है. पोप ने बुधवार को ही एक नाबालिग के 'उत्पीड़न' को लेकर एक अमेरिकी बिशप का इस्तीफा स्वीकार किया था.

'यह अब फिर से कभी नहीं होगा'

पोप ने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अतीत में कुछ लोग गैरजिम्मेदारी, अविश्वास, प्रशिक्षण की कमी, अनुभवहीनता के कारण कई मामलों से गंभीरता और तत्परता से नहीं निपटे. उन्होंने कहा,'यह अब फिर से कभी नहीं होगा. यह पूरे चर्च की पसंद और फैसला है.' पोप ने यह भी आह्वान किया कि पादरियों सहित जिसने भी बच्चों का उत्पीड़न किया है, वह खुद को कानून के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें.

पांडेसरा में भाजपा पार्षद, डाक्टर वानखेडे के हास्पीटल में मरीज की मौत

लापरवाही के चलते हुई मरीज की मौत से परिजनों ने किया तोड़ भोड

साई पालीक्लिनिक पर हमला तथा तोड़ फोड़ से तनाव का माहौल

डॉ. वानखेडे

सूरत। शुक्रवार के शहर के पांडेसरा क्षेत्र स्थित साई पालीक्लिनिक में लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत पर आक्रोशित परिजनों ने हास्पीटल पर हमला कर तोड़ फोड़ शुरु कर दी। पांडेसरा के कार्पोरेटर डॉ. वानखेडे का यह हास्पीटल बताया जा रहा है। इस हास्पीटल में शुक्रवार की सुबह महीज को दाखिल कराया गया। जिसे हास्पीटल की नर्स द्वारा इंजेक्शन लगाते ही मौत हो गई। जिससे परिजन आक्रोशित हो गए। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हास्पीटल में तोड़ फोड़ की। परिजनों के हंगामें को रोकने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पांडेसरा गुजरात हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में संचालित साई पाली क्लिनिक में पेट दर्द के मरीज को दाखिल कराया गया था। पांडेसरा के विसत नगर में रहने वाले 36 वर्षीय महेश भूरा प्रसाद वर्मा को इंजेक्शन लगाने के बाद हास्पीटल की नर्स ने परिजनों से कहा कि 108 द्वारा इसे दूसरे हास्पीटल में ले जाओं। 108 जब तक आती तब तक मरीज की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जैसे ही नर्स ने इंजेक्शन लगाया मरीज की मौत हो गई। इस घटना के बाद मरीज के परिजन तथा संगे सेब घी घटना स्थल पर पहुंच गए और वहां हंगामा करने लगे। मृतक के परिजनों द्वारा हास्पीटल के संचालक तथा क्षेत्र के नगर सेवक को बुलाने की मांग करने पर डाक्टर वानखेडे ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने डाक्टर वानखेडे तथा नर्स को पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने मृतक महेश भूराप्रसाद वर्मा की शव का पंचनामा कर उसे परिजनों के कहने पर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया। अब पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु की सही वजह से पता लग पाएगा।

डॉ. वानखेडे ने भी भीड़ द्वारा हास्पीटल में तोड़ फोड़ की शिकायत पांडेसरा पुलिस में दर्ज कराई है। गौरतलब है कि डाक्टर वानखेडे के पास हास्पीटल चलाने के लिए आवश्यक डीग्री भी नहीं है। होयोपैथिक तथा आयुर्वेदिक की डीग्री लेकर हास्पीटल चलाने वाले वानखेडे की साई पालीक्लिनिक का स्टाफ भी योग्य नहीं है। कम से कम तनख्वाह में काम कनरे वाले स्टाफ के पास आवश्यक डीग्री होगी इसकी कल्पाना भी नहीं की जा सकती। सूरत महानगर पालिका में कारपोरेटर होने के कारण मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी सब जानते हुए भी इसके रसूक के आगे कुछ नहीं कर पाते। सत्ता के मद मे ंचूर डाक्टर वानखेड़े ने केवल गैर कानूनी तरीके से अस्पताल चलाता है बल्कि वह अपनी दबंगई तथा सत्ता का दूरुपयोग करके क्षेत्र में अवैध कब्जे भी करता है। डाक्टर वानखेडे की दबंगई और बाहबुल के आगे क्षेत्र के नागरिक कुछ बोल नहीं पाते। इतना ही नहीं आने बाहुबल और धनबल से यह मनपा के अधिकारियों को कठपूतली की तरह नचाता है। इस फर्जी डाक्टर के विरुद्ध जाने की जो भी कोशिश करते है उसके विरुद्ध फर्जी मामला दर्ज कराकर उसे इतना प्रताड़ित करता है कि वह सपने में भी इसके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करता। डाक्टर वानखेडे पर हुए हमले से क्षेत्र की जनता काफी खुश है। डाक्टर वानखेडे के हास्पीटल में मरीज की मौत की यह पहली घटना नहीं है इसके पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है। परन्तु डाक्टर के भय के चलते किसी ने उसके विरुद्ध शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। अब देखना यह है कि पांडेसरा पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर मृतक के परिजनों को न्याय दिलाती है या पहले की भांति ही डाक्टर को निर्दोष साबित करती है।

श्री उमर वैश्य सेवा समिति के संतोष शाह बने जोड आर.यू.सी.सी के सदस्य

सूरत। पश्चिम रेल्वे के जोनल रेल्वे यूजर कंस्लटेटिव कमेटी (जेड.आर.यू.सी.सी) में शहर के सामान्य परिवार से श्री उमर वैश्य समाज सेवा समिति ट्रस्ट गुजरात के महामंत्री संतोष शाह को पश्चिम रेल्वे द्वारा चुना गया। संतोष शाह को जेड आर.यू.सी.सी का सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव सांसद सी.आर. पाटील द्वारा किया गया था। संतोष शाह की इस उपलब्धि पर गोडादरा में बजरंग सेना द्वारा सम्मान किया गया।

मजूदर पर कुल्हाडी से हमलाकर पिता-पुत्र फरार

सूरत। मांगरोल तालुका के मोर आंबोली गांव स्थित एक दुकान के पास रोड़ पर खुलेआम एक मजदूर पर कुल्हाड़ी से हमला कर पिता-पुत्र ने मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद पिता-पुत्र मौके से फरार हो गये। पुलि ने आई.पी.सी की धारा 325 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार मांगरोल तालुका के मोर आंबली गांव में रहने वाले प्रभूभाई खालवाभाई वसावा दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। प्रभुभाई वसावा के साले का लड़का लालूभाई ने मोर आंबली गांव निवासी बिनूभाई वसावा की पुत्री सुमन बेन के साथ प्रेम विवाह करके भाग गया था। प्रेम विवाह करके पिछले एक सप्ताह से प्रभूभाई वसावा के यहां रह रहे थे। पिछले 4 दिनों से सुमनबेन तथा लालूभाई के साथ बिनू भाई का झगड़ा हो रहा था। गुरुवार को बिनूभाई वसावा तथा उसके पिता सुभाषभाई वसावा ने कहा कि इसने मेरी बेटी को बहुंत तकलीफ दिया है। यह कहते हुए दोनों ने प्रभूभाई के सिर पर ताबडतोड़ कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में प्रभूभाई के सिर में गंभीर चोटे आने से उसने वही दम तोड़ दिया। जिसके बाद दोनों वहां से फरार हो गया। दिन दहाड़े हत्या की इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है।

टी.एम.पटेल स्कूल में स्पोर्टस डे आयोजित

सूरत। शहर के वेसू क्षेत्र स्थित टी.एम. पटेल स्कूल में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्पोर्टस डे का आयोजन किया गया। जिसमें नर्सरी से सातवी तक के विद्यार्थियों ने विविध खेल प्रतियोंगिताओं में भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों के साथ अभिभावकों ने भी खेल का आनंद लिया। माता पिता को ग्राउंड पर दौड़ते देख बच्चे खुब प्रशन्न दिखे। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी दिनेश कदम मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्रिंसिपल सुधा मुरुगकरे द्वारा स्पार्टस पर अपने विचार व्यक्त कर किया गया। खेल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया कार्यक्रम का समापन नृत्य से किया गया।

पूणा-सरोली के-2 मार्केट के बिल्डर के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायत

सूरत। शहर के सरोली क्षेत्र में निर्मित के-2 मार्केट के नाम पर 4 दुकानों की बुर्कींग के 51 लाख रुपये देने वाले ग्राहक ने बिल्डर सुरेन्द्र असीजा के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायत की है। पूणा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार सिटीलाईट आर्शिवाद रेसीडंसी निवासी निरव रतनलाल ने वेसू स्थित कैपिटल ग्रीन अपार्टमेंट निवासी बिल्डर सुरेन्द्र असीजा के खिलाफ विश्वासघात करने का मामला दर्ज कराया है। शिकायत में कहा गया है कि बिल्डर सुरेन्द्र आसीजा ने सारोली में शुरु होने वाले के-2 मार्केट के प्रोजेक्ट में तीन दुकानों की बुंकींग कराया था। जिसके एवज में उसने बिल्डर को 51 लाख रुपये दिए थे। तय समय सीमा से डेढ वर्ष अधिक हो जाने के बाद भी सुरेन्द्र आसीजा ने दुकान का कब्जा नहीं दिया। पुलिस ने फरियादी की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। गौरतलब है कि सूरत में प्रजेक्ट के नाम पर बुकींग की रकम हजम करने की घटनाएं अक्सर देखने को मिल रही है।

साउथ जोन द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्त कर, लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल स्टेट की जगह खाली कराया गया

सूरत। साउथ जोन, उधना के एडीशनल सिटी इंजीनियर तथा जोनल चीफ और कार्यकारी अभियंतना के मार्गदर्शन में शुक्रवार को उधना जोन क्षेत्र अन्तर्गत स्थित लक्ष्मीनारायण इंडस्ट्रीयल स्टेट, बी.आर.सी ग्राउंड, उधना, सूरत में महानगर पालिका की अनुमती के बिना निर्मित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जगह खाली कराया गया। इस जगह पर बिना मंजूरी निर्माण कार्य के विरुद्ध मनपा की तरफ से पहले भी कई बार नोटिस दिया जा चुका है परन्तु मिलकत दारों द्वारा स्वैच्छिक रुप से डिमोलेशन न किए जाने पर उधना जोन के अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जगह खाली कराना पड़ा। इस कार्य में साउथ जोन उधना के तीन डेप्युटी इंजीनियर, 11 असिस्टेंट इंजीनियर, 11 टेक्निकल स्टाफ सहित कुल 307 कर्मचारियों ने मिलकर कुल 45 प्लाटों से अवैध निर्माण का डिमोलेशन कर 19,250 वर्गफूट जगह खाली कराया। डिमोशन खर्च के तौर पर मिलकतदारों के पासे कुल 33,00000 रुपये वसूली किया गया।

मनपा द्वारा लम्बे हनुमान रोड़ पर सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित

सूरत। राज्य सरकार द्वारा अमलीकृत अनेक लोकहितकारी प्रवृतियों तथा प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण के लिए शुक्रवार को लम्बे हनुमान रोड़ पर सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक चले इस कार्यक्रम में नागरिकों की मूल भूत समस्याओं तथा सेवाओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया गया।

इस कार्यक्रम का प्राशंगिक उद्बोधन करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष निरवभाईशाह ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकार तथा सूरत महानगर पालिका की विविध सेवाओं का लाभ सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना है। शासक पक्ष के नेता गिरजाशंकर मिश्रा ने कहा कि सेवा सेतु का मतलब सरकार तथा जनता के बीच जोडने वाला पुल है। लोगों को अलग-अलग समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग जगह न जाना पड़े तथा लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े उसके लिए सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शुक्रवार की सेवा सेतु कार्यक्रम का स्वागत भाषण सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष राश्मिकाबेन पटेल तथा धन्यवाद प्रवचन पार्षद भवानसिंह सिसारा द्वारा किया गया। इस अवसर पर सूरत विधानसभा के विधायक कांतिभाई वलर, बिनूभाई झालावाड़िया, प्रवीण भाई घोघारी दण्डक श्री शासक पक्ष दक्षाबेन जरीवाला, नेताश्री शासक पक्ष गिरजाशंकर मिश्रा, विविध समिति के अध्यक्षों विविध वार्ड के पाषर्दो सहित महानगर पालिका के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सेवा सेतु कार्यक्रम में मेहसूल विभाग, समाज कल्याण विभाग, गुमास्ता विभाग, जिला उद्योग केंद्र, सिटी सर्वे सुप्रिटेंडेंट, आपूर्ति विभाग, व्सवसाय वेरा विभाग, विविध बैंकों, श्रमिक कल्याण बोर्ड, आर. टी.ओ विभाग को मिलाकर कुल 3262 लाभार्थियो को लाभ मिला। जिसमें आय प्रमाणपत्र, क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट, पांचनामा, धार्मिक लघुमति प्रमाण पत्र, विधवा सहाय, वृद्ध सहाय, जाति प्रमाणपत्र बाजपेयी बैकेवल योजना, मानव कल्याण योजना, दिव्यांग सर्टिफिकेट, मां वात्सल्य कार्ड, मां अमृतम कार्ड जैसे विविध प्रश्नों का निराकरण स्थल पर किया गया। इस अवसर पर लाभर्थियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। महानगर पालिका के इस कार्यक्रम को सर्वत्र सराहा जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)